



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं 115]

नई दिल्ली, बृहस्पति, रात, जून 6, 1985/ज्याइस्था 16, 1907

No. 115)

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 6, 1985/JYAISTHA 16, 1907

इस भाग के अलग पृष्ठ रखने का माती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

पूर्व तथा वस्त्र मंत्रालय

(बाल विभाग)

नई दिल्ली, 6 जून, 1985

विषय — वस्त्र नीति विवरण

गफ सं 8/6/85 ट पा सी — भारत सरकार का वस्त्र
नीति विवरण निम्नोक्त प्रकार है —

हमारे देश की अर्थ व्यवस्था में वस्त्र उद्योग अद्वितीय
स्थान रखता है। औद्योगिक उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात
आय में इसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। यह उद्योग जीवन
की एक आधारभूत आवश्यकता की पूर्ति करता है। इसने जो
रोजगार मिलाता है वह लाखों लोगों की आजीविका का साधन
है और इससे अधिकतम लाभ सामान्य तथा मुद्रा क्षेत्रों में
रहते हैं। हमारी कुल वित्तीय मुद्रा आय में एक महत्वपूर्ण
अंश इसके निर्यातों में प्राप्त होता है। अतः हम उद्योग का
स्वस्थ विकास तथा तीव्र वृद्धि अत्यधिक महत्व रखते हैं।

2 गत कुछ वर्षों में वस्त्र उद्योग का विकास मार्च
1981 में वापिस नीति सत्रही ढांचे के आधार पर हुआ है।
जब कि उस नीति सत्रही ढांचे के अन्तर्गत अनेक क्षेत्रों में काफी

प्रगति हुई है वस्त्र नीति विवरण में दी गई वस्त्र नीति के
उद्देश्य पूरी तरह से प्राप्त नहीं किये गये हैं। इस प्रकार
हमारी बाती हुई जनसंख्या के लिये कपड़े की प्रति व्यक्ति
उत्पत्ति और प्रति व्यक्ति खपत अभी भी बहुत नीचे स्तर
पर है। विशेषतः संगठित मिल क्षेत्र में गुणवत्ता के प्रभाव में
वृद्धि का प्रमाण है जो बड़ी संख्या में बन्द फैक्का में मिलता
है। अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों पर विकास संश्लिष्ट तथा ब्लैड
पैन्निक्स के लिये बड़े पैमाने पर मांग पूरी नहीं हुई है जिसे
स्वदेशी उत्पादन द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है। वस्त्र
उत्पादों की पूर्ण निर्यात संभाव्यता का अभी उपयोग में लाया
जाना है।

3 वस्त्र उद्योग को विगत में भी अनेक परिस्थितियों में
उत्तम-चढ़ाव का अनुभव हुआ है। तथापि, इस उद्योग के
सामान्य आ रही विद्यमान कठिनाइयों के एक विश्लेषण में
पता चलता है कि इस उद्योग का वर्तमान महत्व तथा आवृत्ति
है और न ही अपेक्षा की परन्तु उसमें अपेक्षाकृत गहरी संरचनात्मक
रामजोरियों का पता चलता है। अतः सरकार ने
वर्तमान वस्त्र नीति का पुनरीक्षण किया है और ध्यानपूर्वक
विचार करने के बाद अपेक्षाकृत एक दीर्घावधि परिप्रेक्ष्य के

साथ भारत में वस्त्र उद्योग की पुनर्संरचना के लिये यह नई नीति तैयार की है।

4. विद्यमान वस्त्र नीति के अन्तर्गत अनेक उद्देश्य रखे गये हैं। जब कि इनमें प्रत्येक उद्देश्य महत्वपूर्ण है, परन्तु उद्देश्यों की विविधता ने वस्त्र उद्योग के मुख्य कार्य अर्थात् बढ़ती हुई जनसंख्या की कपड़े संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये न्यायोचित कीमतों पर स्वीकार्य क्वालिटी के कपड़े के उत्पादन में वृद्धि को अवरोध कर दिया। अब वे वस्त्र उद्योग के प्रति दृष्टिकोण का मार्गदर्शन इस मुख्य उद्देश्य को लेकर होगा। इस मुख्य उद्देश्य के अनुसरण में उद्योग में रोजगार और उनकी निर्यात संभाव्यता को ध्यान में रखा जाएगा। जनसंख्या के गरीब वर्गों के लिये दे सकने वाली कीमतों पर कपड़े की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी।

5. अब तक वस्त्र उद्योग को या तो विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् संगठित मिलों, विद्युत्करणों तथा हथकरघों के संदर्भ में अथवा रेशा प्रयोग अर्थात् सूती वस्त्रों, ऊनी वस्त्रों, मानव-निर्मित वस्त्रों तथा रेशम वस्त्रों के संदर्भ में उपखंडित रूप में देखा गया है। इस आधार पर वर्गीकरण होने के परिणामस्वरूप वस्त्र उद्योग में संरचनात्मक कठोरताएं आई हैं। उद्योग को एकीकृत रूप में देखने की बजाए उसकी भागों में देखे जाने से उपभोक्ता भाग की पद्धति के अनुरूप प्रौद्योगिकी प्रयोग और उत्पादन-लाभशीलता में अवरोध आता है। इस प्रकार की भिन्नताओं के कारण नीति व्यवस्था की गई है जो क्षेत्र-विशेष या रेशा-विशेष के संदर्भ में है और उससे एक और विशेष हितों तथा दूसरी ओर फासलीकरण का आविर्भाव हुआ है। वस्त्र नीति के मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिये विद्यमान संरचनात्मक कठोरताओं को दूर करना तथा वस्त्र उद्योग का अधिक एकीकृत दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है।

6. वस्त्र उद्योग की प्रस्तावित पुनर्संरचना के निम्नलिखित तीन आयाम होंगे :

- (क) उद्योग को इसकी विनिर्माण प्रक्रिया अर्थात् कटाई, बुनाई तथा संसाधन की अवस्थाओं के संदर्भ में देखा जाएगा;
- (ख) उद्योग को विभिन्न रेशों के प्रयोग में पूर्ण लोच-शीलता प्रदान की जाएगी; और
- (ग) उद्योग प्रतिस्पर्द्धा बढ़ाने तथा उद्योग में स्वस्थ विकास का संवर्धन करने के उद्देश्य से एककों द्वारा क्षमताओं के सर्जन तथा संकुचन के संबंध में अधिक व्यावहारिक नीतियों के अधधीन होगा।

7. कटाई क्षेत्र में, कटाई क्षमता का अनुकुलतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये सभी उपाय किये जाएंगे। कटाई क्षेत्र के लिये कच्चे माल की उपलब्धता बढ़ाई जाएगी। धागे के वितरण के लिये अवस्थापना सुदृढ़ की जाएगी। साथ ही साथ इसकी व्यापक रोजगार संभाव्यता को ध्यान में रखते हुए खादी क्षेत्र में कटाई का प्रोत्साहन देने तथा उसमें वृद्धि करने के लिये आवश्यक उपाय किये जाएंगे।

8. बुनाई क्षेत्र में हथकरघा क्षेत्र की अभिन्न एवं अद्वितीय भूमिका बनाई रखी जाएगी। इस क्षेत्र की वृद्धि तथा विकास को प्राथमिकता दी जाएगी। मिश्रित मिलों तथा शक्तिचालित करघों की अपेक्षा अपनी शक्तिशाली एवं कमजोरियां हैं। नीति के प्रयोजनार्थ, संगठित मिल क्षेत्र में शक्तिचालित करघों तथा असंगठित क्षेत्र के शक्तिचालित करघों को, जहां तक संभव हो सकेगा, बराबर माना जाएगा और उनकी अन्तर्निविष्ट शक्तियों और क्षमताओं के आधार पर उसे पूरा करने की अनुमति दी जाएगी।

9. प्रोसेसिंग क्षेत्र में स्वतन्त्र पावर प्रोसेसर तथा मिलों में प्रोसेसिंग मशीनों को बराबर समझा जाएगा और प्रत्येक को अपनी प्रतियोगी शक्ति के आधार पर चलाने की अनुमति दी जाएगी। सीमित उत्पादन वाले छोटे हंड-प्रोसेसिंग मशीनों पर विशेष रूप से विचार किया जाएगा।

10. पूरी तरह रेशा संबंधी लचीलापन प्रदान करने के लिये अन्तर्निविष्ट बहुरेशा दृष्टिकोण का निम्नलिखित बातों द्वारा मार्गदर्शन किया जाएगा :

- (1) वस्त्र उद्योग को रुई तथा मानव निर्मित रेशों/यार्न के बीच पूरा रेशा लचीलापन प्रदान किया जाएगा। सूती तथा मानव-निर्मित वस्त्रों के संबंध में लाइसेंस प्राप्त एककों को शक्ति रूप में उन के उपयोग में और अधिक रेशा लचीलापन प्रदान किया जाएगा, उनी एककों को पूरा रेशा लचीलापन दिया जाएगा।
- (2) घरेलू उत्पादन बढ़ाकर साथ ही साथ अगर आवश्यक हो तो आयात करके समचित कीमतों पर मानव निर्मित रेशों/यार्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- (3) संश्लिष्ट रेशों/यार्न के उत्पादन के लिये नए एककों द्वारा क्षमता का सर्जन एवं विद्यमान एककों द्वारा क्षमता का विस्तार इस प्रकार निर्धारित किया जाएगा जिससे कि उत्पादन लागतों को कम करने के उद्देश्य में बड़े पैमाने पर होने वाले लाभ प्राप्त किया जा सके।
- (4) मानव-निर्मित रेशों/यार्न पर तथा ऐसे रेशों/यार्न के उत्पादन के लिये अन्तर्निविष्ट साधनों के रूप में उपयोग में लाए जाने वाले मध्यवर्ती पदार्थों पर वित्तीय लेवी को उत्तरोत्तर कम ढंग से कम किया जाएगा जिससे कि बड़े हुए घरेलू उत्पादन को खपाना सुलभ हो सके ताकि संश्लिष्ट और ब्लैंडिड रेशों की कम कीमतों के रूप में यह लाभ उपभोक्ता को मिल सके, और
- (5) मानव-निर्मित रेशों/यार्न के लिये निर्यात छला रखा जाएगा।

11. वस्त्र उद्योग के मुख्य कच्चे माल के रूप में रई की सर्वोत्तम भूमिका बनाई रखी जाएगी। रई के घरेलू खपत द्वारा तथा रई, यार्न और अन्य उत्पादों के निर्यात द्वारा स्वदेशी रई के उपयोग का सुनिश्चित किया जायगा। रई उपजकर्ताओं को लाभकारी कीमतों पर सदैव उसके उत्पाद की उठान सुनिश्चित करानी होगी। वस्त्र उद्योग द्वारा अपेक्षित रई पर्याप्त मात्रा में तथा समचित कीमतों पर उपलब्ध कराई जाएगी। भारतीय रई निगम की भूमिका तथा कार्य, कीमत स्थिरीकरण कार्य का शामिल करने के लिये पुनः प्रतिपादित किया जायेगा। इस उद्देश्य के लिये, निगम का निश्चित रूप से अन्तराष्ट्रीय बाजारों में प्रवेश करना पड़ेगा। रई के वर्तमान किस्म संबंधी अमनुलन का नीतियों के मेल में ठीक किया जाएगा जिसका उद्देश्य एक ओर लंबे तथा अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों की रई का उपयोग बढ़ाने को प्रोत्साहन देना है तथा दूसरी ओर छार्टी तथा मध्यम स्टेपल किस्मों का अधिक उत्पादन करना है।

12 एम. आर. टी. पी. अधिनियम तथा एफ. ई. आर. ए. के उपबंधों को शामिल करके सामान्य औद्योगिक नीतियों के अधीन विद्यमान एकको द्वारा क्षमता का विस्तार तथा नए एकको द्वारा क्षमता का संयोजन करने की अनुमति दी जाए। मिडिल जप म. एवका की क्षमताओं की सविता करने की भी अनुमति होगी जिसमें ताजा कच्ची आवश्यक तथा औचित्य हो, एकको अथवा उनके भाग को बन्द करना शामिल है। वगैरे कि कामगारों के हितों की पूर्ण संरक्षण दिया गया हो। इस प्रक्रिया में उद्योग में एकको के बीच प्रतिस्पर्धा के स्तर में वृद्धि होगी तथा लागत में कमी और क्वालिटी में सुधार का वातावरण तैयार होगा।

13. असंगठित क्षेत्र में बिजली करघों की गैर-योजना-बद्ध वृद्धि अधिकांशतया कुछ शहरों में केन्द्रित है। बिजली करघे काफी उत्पादन में अभी भी अपजीकृत तथा अनधिकृत हैं। इस लिए सभी अत्र में बिजली करघों के लिये पंजीकरण अनिवार्य होगा। बिजली करघा क्षेत्र में उत्पादन के संगठन का मार्गदर्शन, उत्पादकता बढ़ाने, कार्यकुशलता बढ़ाने, कामगारों के कल्याण कार्य में सुधार करने तथा स्थान वार आंदोलन को सुकर बनाने के उद्देश्य से किया जा रहा है। इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बिजली करघा क्षेत्र के लाभप्रद विकास के लिए उपयुक्त उपाय पैकेज तैयार किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिजली करघे उद्योगों के लिये स्थान संबंधी विशेष रूप से बड़े शहरों और महानगरों में मार्गदर्शी मिडिल्टी का उत्पादन न करे। यह देखने के लिए कारगर उपाय किये जाएंगे कि बिजली करघे, हथकरघों द्वारा अन्त्य तौर पर उत्पादन करने के लिये सुरक्षित वस्तुओं को अपने अन्तर्गत न लें। इस उद्देश्य के लिये संगठनात्मक ढांचे को मजबूत किया जायेगा।

14. हथकरघों की अर्द्धनिर्मित भूमिका बनाये रखने और उन्हें उनका पूर्ण सम्भावित प्रोत्साहन और साथ ही

हथकरघा बुनकरों के लिये बेहतर आय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए जाएंगे :

- (1) सहकारी समितियों तथा केन्द्रीय राज्य स्तर के निगमों की मार्फत हथकरघों के विपणन को तेज किया जायगा ;
- (2) करघों के आधुनिकीकरण तथा हथकरघों की उत्पादकता और हथकरघा उत्पादों की क्वालिटी तथा फिनिश में सुधार के लिये प्रौद्योगिकीय तथा निविष्ट साधनों की व्यवस्था पर अधिक ध्यान दिया जाएगा ;
- (3) हथकरघा क्षेत्र को यार्न तथा अन्य कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिये विशेष प्रयास किये जाएंगे। राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम तथा राज्य स्तर के हथकरघा अधिकरणों के कार्यों द्वारा ऐसे कच्चे माल की उचित कीमतों पर खरीद तथा सप्लाय के लिये अवस्थापना को मजबूत किया जाएगा ;
- (4) बुनकरों की मजदूरी तथा आय में सुधार करने के उद्देश्य से हथकरघों पर मिश्रित तथा ब्लेड्ड वस्तु के उत्पादन की प्रोत्साहन दिया जाएगा ;
- (5) हथकरघा (उत्पादन के लिये वस्तुओं का आरक्षण) अधिनियम, 1985 के अंतर्गत हथकरघा क्षेत्र में अन्त्य तौर पर उनके उत्पादन के लिये वस्तुओं के आरक्षण द्वारा हथकरघों को आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधानों को सही से लागू किया जाएगा तथा इस कार्य को करने वाली व्यवस्था को उचित रूप से सुदृढ़ किया जाएगा।
- (6) हथकरघों की प्रतियोगिता क्षमता में सुधार लाने के लिये उपयुक्त राजकोषिय उपायों द्वारा शक्ति-शालित करघों की तुलना में हथकरघों की लागत संबंधी बाधा को यथासंभव दूर करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ;
- (7) हथकरघों उत्पादों के विपणन में सुधार लाने के लिए विपणन कम्प्लेक्सों की अस्थापना, विपणन कर्मचारियों के प्रशिक्षण और गहन प्रचार की व्यवस्था की जाएगी। हथकरघा क्षेत्र में लगे कर्मचारियों के तकनीकी, प्रबंध संबंधी और प्रशासनिक हुनरों को अपग्रेड करने के उपाय किये जाएंगे ;
- (8) हथकरघा विकास कार्यक्रमों की बेहतर योजना बनाने और उनके कार्यान्वयन के लिये हथकरघा क्षेत्र के आंकड़ा आधार को मजबूत बनाने के उद्देश्य से हथकरघों की गणना आरम्भ की जाएगी। हथकरघा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन निगरानी और मूल्यांकन के लिये मशीनरी को मजबूत बनाया जाएगा।

15. हथकरघा बुनकरों की कार्य स्थितियों में सुधार करने और उन्हें प्रत्यक्ष लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से अन्य योजनाओं के अलावा निम्नलिखित योजनाएँ शुरू की जाएंगी :—

- (1) अणुदात्री वस्त्र निर्धि योजना ताकि जरूरत पड़ने पर हथकरघा बुनकरों को सहायता प्रदान की जा सके।
- (2) बकंगड-सह-आवास योजना ताकि हथकरघा बुनकरों को कार्य तथा रहने के लिये बेहतर स्थान प्रदान किये जा सकें।

16. मानवी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्यात कपड़े के उत्पादन का संपूर्ण उत्तरदायित्व हथकरघा क्षेत्र को हस्तान्तरित किया जायेगा। समाज के गरीब वर्गों को उनके द्वारा दी जा सकने वाली कीमतों पर कपड़े की बड़ी मात्रा प्रदान कराने के उद्देश्य से निर्यात तथा जनता कपड़े की निर्धारित 650 मिलियन मीटर की मात्रा में उचित वृद्धि की जायेगी। कपड़े की क्वालिटी में सुधार लाने पर और यह सुनिश्चित करने के लिये उपाय किये जाएंगे कि वह लक्ष्य समूह तक पहुँचे। कंट्रोल के कपड़े के सार्वजनिक वितरण को मजबूत और सरल व कारगर बनाया जायेगा।

17. ग्रामीण क्षेत्रों में खादी के बड़े काम और आय सृजन सम्भाव्यता, विशेषतः महिलाओं के लिये, को देखते हुए, खादी कार्यक्रम के विकास को सभी प्रोत्साहन दिए जायेंगे। खादी कार्यक्रम के अंतर्गत, उत्पादन प्रक्रिया को सुधारने, उत्पादकता को बढ़ाने, श्रमिकों के हुनर को उत्तन करने, उत्पाद क्षेत्र के विविधीकरण और विपणन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे।

18.1 वस्त्र उद्योग विशेष रूप से संगठित मिल क्षेत्र में बढ़ती हुई रुग्णता का प्रभाव बहुत ही चिन्ता का विषय है। रुग्णता के अनेक तथा जटिल कारण हैं जिनमें शामिल है वित्तीय कठिनाइयाँ, प्रबंध संबंधी अक्षमता और लापरवाही अर्थात् समय व मशीनें, अपर्याप्त रख-रखाव रखन उत्पाद मिश्रण कम विपणन श्रमिकों की बहुलता, खराब औद्योगिक संरचना। जबकि समग्र उद्योग के स्वास्थ्य में सुधार करने तथा रुग्णता को रोकने के लिये आवश्यक उपायों को उल्लेख इस विवरण में किया गया है एकक की विशिष्ट समस्याओं का समाधान अलग अलग प्रत्येक मामले के आधार पर निकाला जायेगा।

18.2 रुग्ण एकक को पुनः जीवित करने के लिये आवश्यक उपायों को उन कारणों के विस्तृत और वस्तु परक अध्ययन पर आधारित रखना होगा जिनसे एकक रुग्ण बना और ऐसे उपायों का पता लगाना होगा जो रुग्ण एकको को अर्थक्षम करने के लिये आवश्यक है। ऐसे एककों के बीच मदो भेद करना होगा जो संभाव्य रूप से अर्थक्षम है और अर्थक्षम नहीं है।

18.3 संभाव्य रूप से अर्थक्षम एककों के मामले में पुनर्स्थापन संबंधी उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ ये

शामिल होंगे; अनिवार्य बेल्टिंग उपकरणों की व्यवस्था, वर्तमान मशीनरी का प्रतिस्थापन, उत्पाद समूह में परिवर्तन विपणन की बेहतर नीति, प्रबंध का मजबूत बनाया जाना और उत्पादन का विभिन्न अवस्थाओं में क्षमता का सफेद और समायोजन। ऐसे मामलों में उपर्युक्त वित्तीय सुविधाओं के जुटाए जाने की आवश्यकता होगी। इन सुविधाओं को जुटाने और उनका प्रबंध करने के लिये तीव्र ऐजेंसी नियुक्त की जाएगी। ऐसे एककों के वित्तीय और तकनीकी कार्य निष्पादन को संचालनापूर्वक मॉनिटरिंग की जायेगी।

18.4 कुछ मामलों में, सक्षमता की सम्भाव्यता होते हुए भी ये एकक अनुपयुक्त प्रबंध अथवा अवस्था की वजह से रुग्ण हो गये होंगे। ऐसे मामलों में, वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे उन मामलों में परिवर्तन अनिवार्य होगा जहाँ पूजा का तथा दाकियों का पुनर्भरण अपेक्षित होगा।

18.5 इपनीति में निरूपित उपायों से कुछ एकक अपनी वर्तमान कठिनाई पर काबू पाने में सक्षम होंगे। तथापि, जहाँ किसी एकक को पर्याप्त समयावधि में जीवनक्षम होने की आशा न हो वा उस स्थिति में उस एकक बंद करने के अलावा अन्य कोई विकल्प न होगा बशर्ते कि श्रमिकों के हितों की रक्षा हो। ऐसे रुग्ण एककों की सरकार द्वारा अधि-गृहित करना अथवा उनका राष्ट्रीकरण करना रुग्णता की समस्या का समाधान नहीं है तथा नियमानुसार ऐसे मामलों में सन्तुष्ट हस्तक्षेप भी नहीं करेगी।

18.6 रुग्ण एककों के पुनरुद्धार की प्रक्रिया के दौरान तथा इन्हें बंद करने अथवा परिष्कार करने में श्रमिकों के हितों की पूरा रक्षा की जाएगी। वस्त्र उद्योग की रूढ़िवादी में निहित परिवर्तन का सामाजिक लागतों को न्यूनतम करने के लिये छंटनों से पूर्व सभी संभव पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिये। एक संतापजनक समाधान निकालने के लिये श्रमिक यात्राकीकरण और कार्यमानदण्ड में सुधार के लिये श्रमिकों के साथ बातचीत की आवश्यकता होगी। श्रमिकों को छंटनी के भुगतान के लिये निधियों की आवश्यकता, पुनर्स्थापना कार्य का भाग होगी और ऐसी प्रतिपूर्ति के लिये आवश्यक ऋण रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराये जायेंगे। एक प्रबंध के अंतर्गत अन्य एककों में अथवा एक ही क्षेत्र में अन्य आद्योगिक एककों में रोजगार दिये जाने में हटाये गये श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी। स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये रियायती वित्त उपलब्ध कराया जाएगा। कामगारों का पूरे अथवा आंशिक एकको का चयन के लिये सहकारी समितियाँ बनाने के लिये भी प्रोत्साहित किया जायेगा पुनर्नियोजन का सरल बनाने के लिये श्रमिकों का प्रशिक्षण और पुनः प्रशिक्षण के लिये योजनायें तैयार की जाएंगी।

18.7 यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एककों के स्थायी तौर पर बंद हो जाने से जो कामगार प्रभावित होते हैं उनके हितों की सुरक्षा को जाननी है। उन कार्यों के लिये कानूनी

लाभों के अनिवार्य अवधि के लिये सहायता प्रदान करने के लिये योजनाएँ बनायी जाएँ। ऐसे कामगारों का एक सीमित अवधि के लिए सहायता प्रदान करने के लिये वस्त्र उद्योग के कामगारों के लिए एक पुनः स्थापना निधि बनाई जाएगी। ऐसी निधि अन्य बातों के साथ-साथ वस्त्र उद्योग पर एक उपयुक्त उपकरण द्वारा वित्त पोषित की जाएगी।

18.8 वार्षिक गणना का पता लगाने के लिए वस्त्र एकका के कार्य उत्पादन की निष्पत्ति में मापने के (संचालित करने) की आवश्यकता है ताकि समय से ही उचित उपाय किये जा सकें। इस प्रयोजन के लिये विभिन्न स्तरों पर संतुलित संरचना को मजबूत किया जाएगा।

19.1 उद्योग की वर्तमान स्थितियों के प्रमुख कारणों में से एक है अपर्याप्त आधुनिकीकरण तथा पुनर्गठन अप्रचलित संयंत्र और मशीनरी का नवीकरण। सरकार द्वारा प्रेरणा तथा प्रोत्साहन देने के बावजूद भी उद्योग का कुछ हद तक ही आधुनिकीकरण हुआ है। सरकार की नीतियों का लक्ष्य उद्योग के आधुनिकीकरण की गति को त्वरित करना होना चाहिए।

19.2 ओटाई क्षेत्र में थाटा या आधुनिकीकरण हुआ है, जिससे र्थ की क्वालिटी पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के कारण उद्योग के अंतिम उत्पाद पर प्रभाव पड़ा है। विद्यमान ज़िम्मेदारियों के तेजी से प्रतिस्थापन तथा आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए रियायती वित्त उपलब्ध कराया जाएगा।

19.3 प्रत्येक एकक में सतुलन के उपकरणों के प्रतिस्थापन, वर्तमान मशीनरी के नवीकरण, प्रतिस्थापन तथा प्रौद्योगिकी स्तरों के नवीकरण जैसी ध्यानपूर्वक अभिजात की गई आवश्यकताओं के आधार पर बनाई, बनाई तथा समाधान क्षेत्रों में आधुनिकीकरण किया जाएगा।

19.4 आधुनिकीकरण के प्रयोजन के लिए, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की उदार ऋण योजना के अन्तर्गत पर्याप्त उपाय के रूप में काफी धनराशि दी जाती रहेगी। उद्योग आधुनिकीकरण के लिए आन्तरिक समाधान उपलब्ध कर सके इसके लिए एक वस्त्र आधुनिकीकरण कोष बनाया जाएगा।

19.5 वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थायी परामर्शदात्री समिति बनाई जाएगी, जिसमें प्रबन्ध तथा श्रमिक प्रतिनिधि और साथ ही उपयुक्त तकनीकी विशेषज्ञ और विनीय संस्थानों के प्रतिनिधि भी होंगे। यह समिति आधुनिकीकरण की ओर जिस किस्म का आधुनिकीकरण उद्योग का अपनाया चाहिए, उसकी जरूरतों का सतत आधार पर पता लगाएगी।

19.6 यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आधुनिकीकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया में श्रमिकों के हितों का पर्याप्त सुरक्षा हो।

19.7 घरेलू वस्त्र मशीनरी विनिर्माण उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाएगा ताकि मशीनरी की लागत कम हो, प्रौद्योगिकी उन्नत हो और क्वालिटी में सुधार हो। तथापि, जिस घरेलू मशीनरी का दश में विनिर्माण नहीं होना उनको अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों अथवा उनके नगरीय कीमतों पर आयात करने की उदारतापूर्वक अनुमति दी जाएगी।

19.8 हथकरघा के शीघ्र आधुनिकीकरण के लिए, सुधरे किस्म के हथकरघों का विकास करने के लिए अनुसंधान और अनुसंधान समस्याओं में हथकरघा बनकरों का प्रौद्योगिकी का शीघ्र और निरन्तर अन्वेषण सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था करने के काम का प्राथमिकता दी जाएगी।

19.9 अधिक विद्युत्करण सेवा केन्द्र स्थापित किए जाएंगे ताकि विद्युत्करण बनकर उपकरण के रखरखाव, डिजाइन विकास और बनाई की क्वालिटी के संबंध में अपने हस्त में सुधार कर सकें।

19.10 वस्त्र अनुसंधान एसोसिएशन आधुनिकीकरण की प्रक्रिया और उसकी मापदंडों में सक्रिय रूप से काम करेंगे तथा उनकी भूमिका में विस्तार किया जाएगा ताकि वे हथकरघों और विद्युत्करण की जरूरतों की भी पूर्ति कर सकें।

20 राष्ट्रीय वस्त्र निगम संगठित क्षेत्र में यान और वस्त्रों के कुल उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान करता है। एन टी सी के अधीन र्थ मिले पुनर्स्थापित के कार्यक्रम के जरूरत नुकद हानियों को समाप्त करने में सफल हुई है। चयनात्मक आधुनिकीकरण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए बेहतर प्रयास की जरूरत है ताकि अधिक से अधिक एकक लाभ-प्रद बन सकें। ऐसे एककों को, जोकि अर्थक्षम बनने में सक्षम नहीं हैं, बराबर चलाने रहने का अर्थ होगा दुर्लभ स्रोतों का सतत प्रयत्न तथा ऐसे एककों अथवा उसके भागों को बन्द किया जा सकता है ताकि कोई और हानियाँ न हों। ऐसे मामलों में श्रमिकों के हितों की पर्याप्त रक्षा की जाएगी। उपकरण के आधुनिकीकरण प्रबन्ध से सुदृढीकरण करना और सुधार, श्रमिकों को उत्पादकता को बढ़ाने तथा कार्य दक्षिण में सुधार के कार्यक्रम का कार्यान्वयन करने में ऐसी आशा है कि एन टी सी वस्त्र उद्योग में स्थिरता और स्वस्थ प्रतियोगिता लाने में योग देगा।

21. वस्त्र क्षेत्र के निर्यात का निर्यातों में प्राप्त होने वाली कुल विदेशी मुद्रा आय में महत्वपूर्ण भाग है। तथापि, आन्तरिक और बाहरी दोनों प्रकार की कुछ बाधाएँ हैं जिसके परिणामस्वरूप अब तक वस्त्र निर्यातों की पूरी सम्भाव्यता का लाभ नहीं उठाया जा सका है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार विश्व वस्त्र व्यापार को उदार बनाने का

प्रयास करेगी जिससे हमारे निर्यातों के संबंध में बाहरी बाधाएँ कम होंगी। घरेलू क्षेत्र में, इस क्षेत्र में तुलनात्मक लाभ उठाने के लिए तथा विश्व बाजार में क्वालिटी तथा दोनों दृष्टियों में वस्त्रों के अधीन निर्यातों को अधिक प्रतियोगी बनाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इस प्रयोजन के लिए, नीति ढाँचे में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि निर्यात उत्पादन के लिए अन्तर्निविष्ट साधन, जिनमें पूँजीगत माल भी शामिल है, अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों पर अथवा उसके लगभग कीमतों पर उपलब्ध किए जाएँ। इसी प्रकार उत्पाद और बाजार विकास में तीव्र प्रयास करना, विपणन नीति का तथा रूप देना तथा फेशन और डिजाइन विकास के लिए क्षमताओं का मूँज करना आवश्यक होगा। हथकरघा क्षेत्र के उत्पादों जिनमें रेशम उत्पाद भी शामिल है, के निर्यात की विश्व बाजार में काफी संभाव्यता है। इस संभाव्यता का लाभ उठाने में सहायता देने के लिए पूरा प्रोत्साहन दिया जाएगा चूंकि निर्यात उत्पादन उद्योग में कुल उत्पादन आधार का अभिन्न अंग है, वस्त्र उद्योग की पुनः संरचना और उसके आधुनिकीकरण के लिए इस विवरण में जो उपाय बताए गए हैं, उनमें निर्यात को आवश्यक प्रोत्साहन मिलेगा।

22. ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की रोजगार सभाव्यता, अधिक आय सृजित करने की उम्मीद क्षमता और निर्यातों के जरिए मुख्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने के उसके सामर्थ्य का देखते हुए सरकार रेशम उत्पादन के विकास पर बराबर बल देती रही है। देश के सभी भागों में इस उद्योग के तीव्र विकास के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा राज्य सरकारों को प्रोत्साहन तथा सहायता दी जाती रहती है। क्वालिटी बीजों के उत्पादन, मुधरी किस्मों के रंफण तथा अधिक क्षेत्रों में रेशम उत्पादन कार्यकलापों के विस्तार तथा प्रति हेक्टेयर अधिक उपज की प्राप्ति में संबंधित योजनाओं पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। किसानों को रेशम कीट पालन तथा रोगों के नियन्त्रण की मुधरी तकनीकों की किसानों को शिक्षा देने के लिए मौजूदा विस्तार तथा प्रशिक्षण को मजबूत बनाया जाएगा। रेशम वस्त्र की क्वालिटी में सुधार लाने के लिए रीलिंग, बुनाई तथा प्रोसेसिंग की प्रौद्योगिकी के विकास के लिए प्रयास किए जाएंगे।

23. सरकार अधिक तौर पर कमजोर वर्गों विशेषतः देश के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वालों को न्यायोचित मूल्यों पर ऊनी कपड़ों तथा कम्बलों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य में ऊनी वस्त्र क्षेत्र के विकास का संबंधन करती रहेगी। मात्रा तथा क्वालिटी दोनों दृष्टि से कच्ची ऊन के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यक्रम चलाए जाएंगे। चूंकि उद्योग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कच्ची ऊन का स्वदेशी उत्पादन काफी नहीं है, अतः अच्छी क्वालिटी की ऊन तथा साथ ही शाडी के आयातों के सम्बन्ध में उदार नीति कायम रखी जाएगी। अनुसन्धान तथा विकास कार्यक्रमों का संबंधन किया जाएगा ताकि अपेक्षाकृत सस्ते तथा बेहतर क्वालिटी के

ऊनी उत्पादों का घरेलू तथा साथ ही निर्यात बाजारों के लिए विकास किया जा सकता है।

24. बुनाई तथा परिधान विनिर्माता क्षेत्रों का कपड़े की घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा रोजगार सृजन तथा निर्यात आय में महत्वपूर्ण योगदान है। सरकार इन क्षेत्रों के सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण तथा विकास के लिए नीतियों का अनुसरण करेगी।

25. एक अधिक गुणवत्ता प्रणाली, जो लागतों तथा माजिनों को कम करेगी और जिसमें उपभोक्ता सन्तुष्टि तथा उभाक्ता संरक्षण दोनों उपलब्ध होंगे, के उद्देश्य में यथा आवश्यक रूप में परिवर्तन लाने के लिए उद्योग की मौजूदा विपणन तथा वितरण प्रणाली का पुनरीक्षण किया जाएगा। बाजार अनुसंधान के लिए संस्थागत व्यवस्थाओं को सुदृढ किया जाएगा।

26. वस्त्र उद्योग पर अनेक नियन्त्रण तथा विनियम लागू किये जाते रहे हैं जिनमें से बहुत से समय गुजरने के साथ असंगत या अनावश्यक हो गए हैं। इस प्रकार के नियन्त्रणों को हटाने, धीरे-धीरे कम करने अथवा उनमें संशोधन करने के लिए, जैसा भी मामला हो, उनकी समीक्षा की जाएगी।

27. सरकार का अंशा है कि उपर दी गई नीति व्यवस्था में भारत में वस्त्र उद्योग की आवश्यक पुनर्संरचना में सुविधा होगी, देश में उत्पादन, रोजगार तथा निर्यातों में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण योगदान करने के लिए वस्त्र उद्योग साधनयुक्त होगा और जनसंख्या के सभी वर्गों की कपड़ा संबंधी जरूरतों का यह उद्योग पूरा करेगा।

जे. के. बागची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SUPPLY AND TEXTILES

(Department of Textiles)

New Delhi, the 6th June, 1985

Subject.—Statement on Textile Policy.

F. No. 8/6/85-TPC.—The Statement of Textile Policy of the Government of India is as under :—

The textile industry has a unique place in the economy of our country. Its contribution to industrial production, employment and export earnings is very significant. This industry provides one of the basic necessities of life. The employment provided by it is a source of livelihood for millions of people, most of whom live in rural and remote areas. Its exports contribute a substantial part of our total foreign exchange earnings. The healthy development and rapid growth of this industry is, therefore, of vital importance.

2. In the past few years, the development of the textile industry has been guided by the policy framework announced in March 1981. While considerable progress has since been achieved in several areas

under this policy frame-work, the objectives of the textile policy outlined in the Textile Policy Statement have not been fully achieved. Thus, the per capita availability for and the per capita consumption of cloth, of our growing population, still remain at a very low level. There is evidence of an increase in the incidence of sickness, particularly in the organised mill sector, reflected in a large number of closed units. There is a large unsatisfied demand for durable synthetic and blended fabrics at cheaper prices which is not being met by indigenous production. The full export potential of textile products remain to be realised.

3. The textile industry has experienced fluctuations in its fortunes in the past also. However, an analysis of the current difficulties faced by the industry reveals that the present crisis of the industry is, neither cyclical nor temporary, but suggests deeper structural weaknesses. Therefore, the Government have reviewed the present textile policy and after careful consideration, have formulated this new policy for the restructuring of the textile industry in India with a longer term perspective.

4. The existing textile policy sets out a number of objectives. While each of these objectives is important, the multiplicity of objectives has inhibited the achievements of the main task of the textile industry, that is to increase the production of cloth of acceptable quality at reasonable prices to meet the clothing requirements of a growing population. Henceforth the approach to the textile industry would be guided by this main objective. In the pursuit of this main objective, the employment and export potential of the industry shall be kept in view. The availability of cloth at affordable prices for the poorer sections of the population shall be augmented.

5. The textile industry has, so far, been viewed in a compartmentalised manner either in terms of various sectors, namely, organised mills, powerlooms and handlooms, or in terms of fibre use, namely, cotton textiles, woollen textiles, man-made textiles, and silk textiles. Classification on such grounds have led to structural rigidities in the textile industry. When the industry tends to be viewed in parts rather than as an integrated whole, it inhibits the technology use and production-flexibility commensurate with the pattern of consumer demand. Such distinctions have led to the application of a policy mix which is sector-specific or fibre-specific resulting in the emergence of special interests on the one hand and fossilisation on the other. To achieve the main objective of the textile policy, it is necessary to eliminate the existing structural rigidities and to evolve a more integrated view of the textile industry.

6. The proposed restructuring of the textile industry would have the following three main dimensions :—

- (a) the industry shall be viewed in terms of the stages of its manufacturing process, namely, spinning, weaving and processing;
- (b) the industry shall be provided with fuller flexibility in the use of various fibres; and

- (c) the industry shall be subject to more pragmatic policies regarding creation or contraction of capacities by units in order to increase competition and promote healthy growth in the industry.

7. In the spinning sector, all steps will be taken to ensure optimum utilisation of the spinning capacity. The availability of raw materials for the spinning sector would be augmented. The infrastructure for the distribution of yarn would be strengthened. At the same time, necessary measures to encourage and increase spinning in the Khadi sector would be taken in view of its large employment potential.

8. In the weaving sector, the distinct and unique role of the handloom sector shall be preserved. The growth and development of this sector shall receive priority. The composite mills and the powerlooms have their own respective strength and weaknesses. For the purpose of policy, powerlooms in the organised mill sector and in the unorganised powerloom sector shall, as far as possible, be treated at par and allowed to compete on the basis of their inherent strengths and capabilities.

9. In the processing sector, the independent power processors and the processing houses in the mills would be treated at par and each would be allowed to operate on the basis of its competitive strength. The small hand-processing units with limited output will receive special consideration.

10. The multi-fibre approach implicit in providing fuller fibre flexibility would be guided by the following considerations :—

- (i) Full fibre flexibility as between cotton and man-made fibres/yarn would be provided to the textile industry. Greater fibre flexibility in the use of wool shall be provided in a phased manner to units licensed for cotton and man-made textiles. woollen units shall be given full fibre flexibility;
- (ii) Adequate availability of man-made fibres/yarn at reasonable prices shall be ensured by increased domestic production supplemented as necessary by imports;
- (iii) Creation of capacity by new units and expansion of capacity by existing units for production of synthetic fibres/yarn would be so determined as to realise economies of scale in order to reduce costs of production;
- (iv) Fiscal levies on man-made fibres/yarn, and on the intermediates used as inputs for the production of such fibres/yarn, shall be progressively reduced in such a manner as to facilitate absorption of increased domestic production so that the benefit flows to the consumer in the form of lower prices of synthetic and blended fabrics; and
- (v) The export window shall be kept open for man-made fibres/yarn.

11. The pre-eminent role of cotton as the main raw material of textile industry would be maintained. Utilisation of indigenous cotton would be ensured by domestic consumption and by export of cotton, yarn and other manufactures. Cotton growers shall always be assured off-take of their produce at remunerative prices. Cotton needed by the textile industry would be made available in adequate quantity and at reasonable prices. The role and functions of the Cotton Corporation of India would be reformulated to include price stabilisation operations. For the purpose, the Corporation would have the necessary access to international markets. The present varietal imbalance of cotton shall be corrected by a mix of policies aimed at encouraging increased use of long and extra-long varieties of cotton on the one hand and higher production of short and medium staple varieties on the other.

12. Capacity expansion by existing units and capacity creation by new units would be permitted subject to the general industrial policies including the provisions of the MRTP Act and FERA. As a corollary, units would also be allowed to contract capacities, including closure of a unit or part thereof, wherever necessary and justified, provided the interests of the workers are fully protected. This approach would increase the degree of competition among units in the industry and create an environment conducive to a reduction in cost and an improvement in quality.

13. The unplanned growth of powerlooms in the unorganised sector has mostly tended to concentrate in a few areas. A significant proportion of the powerlooms remain unregistered and unauthorised. Henceforth, there shall be compulsory registration of all powerlooms. The organisation of production in the powerloom sector should be guided by the objectives of raising productivity, increasing efficiency, improving workers' welfare and facilitating locational dispersal. In keeping with these objectives, a suitable package of measures would be evolved in order to bring about a healthy development of the powerloom sector. It would be ensured that powerloom do not violate the locational guidelines for industries, particularly in large cities and metropolises. Effective measures would be taken to see that the powerlooms do not encroach upon articles reserved for exclusive production by the Handloom. The organisational set-up required for the above purposes shall be strengthened.

14. In order to preserve the unique role of Handlooms and enable them to realise their full potential as also to ensure higher earnings for the handloom weavers, the following main steps shall be taken :—

- (i) The development of handlooms through Cooperatives and Central/State level Corporations shall be intensified.
- (ii) Greater emphasis will be placed on the modernisation of looms and provisions of technological and other inputs for improving productivity of handlooms and the quality and finish of handloom products ;
- (iii) Special efforts would be made to ensure adequate availability of yarn and other raw

materials to the handloom sector. The infrastructure for procurement and supply of such inputs at reasonable prices to the handloom weavers shall be strengthened through the operations of the National Handloom Development Corporation and State level handloom agencies ;

- (iv) The production of mixed and blended fabrics on handlooms shall be encouraged with a view to improve the wages and earnings of the weavers ;
- (v) Protection to handlooms will be provided by reserving articles for their exclusive production in the handlooms sector under the "Handloom (Reservation of Articles for Production) Act, 1985". The provisions of this Act shall be strictly enforced and the machinery for doing so shall be suitably strengthened ;
- (vi) To improve the competitiveness of handlooms steps would be taken to remove, as far as possible, the cost handicap of the handlooms vis-a-vis the powerlooms by suitable fiscal measures ;
- (vii) To improve the marketing of handloom products, infrastructure of marketing complexes, training of marketing personnel and intensive publicity shall be organised. Steps would be taken to upgrade the technical, managerial and administrative skills of personnel employed in the handloom sector ;
- (viii) to strengthen the data base for the handloom sector for better planning and execution of handlooms development programmes, a census of handloom shall be undertaken. The machinery for implementation, supervision and evaluation of handloom programmes shall be strengthened.

15. In order to improve the working conditions of the handloom weavers and to provide direct benefit to them, the following schemes, amongst others, would be introduced :

- (i) Contributory Thrift Fund scheme to provide assistance to the handloom weavers during times of need ;
- (ii) a Workshed-cum-Housing scheme to provide a better place for work and living to the handloom weavers.

16. The responsibility for the entire production of controlled cloth shall be transferred to the handloom sector by the end of the Seventh Five Year Plan. The quantum of controlled cloth and Janta cloth which was fixed at 650 million metres shall be suitably increased in order to provide a larger quantum of cloth at affordable prices to the poorer sections of the population. Measures will also be taken to improve the quality of cloth and to ensure that it reaches the target group. The public distribution for controlled cloth would be strengthened and streamlined.

17. All encouragement would be given to the expansion of the Khadi programme in view of its large employment and income generating potential in the

rural areas, specially among women. Steps would be taken to improve the production process, upgrade the skills of workers, raise productivity, diversify the product range and strengthen the marketing arrangements under the Khadi programme.

18.1 The incidence of growing sickness in the textile industry, particularly in the organised mill sector, is a matter of great concern. The reasons for sickness are manifold and complex which include financial difficulties, managerial incompetence and negligence, obsolete plant and machinery, inadequate maintenance, incorrect product-mix, poor marketing, excess labour and poor industrial relations. While steps necessary to improve the health of the industry as a whole and to prevent sickness as are indicated in this Statement, unit specific problems would have to be tackled on a case to case basis.

18.2 The measures needed for the revival of a sick unit have to be based on a detailed and objective study of the causes that led to sickness, and identification of the steps necessary to revive the sick unit. A distinction shall have to be made between units which are potentially viable and units which are not.

18.3 In the case of potentially viable units a rehabilitation package might, inter alia, comprise of provision of additional balancing equipment, replacement of existing machinery, change of product-mix, better marketing strategy, rationalisation of labour including improvement of work-norms, strengthening of management and organisation and adjustment of capacity in the different stages of manufacturing. In such cases, suitable financial package would need to be worked out. A nodal agency would be designated to evolve and manage this package. The financial and technical performance of such units shall be closely monitored.

18.4 In some cases, the units, although potentially viable, may have been led to sickness by inept management or mismanagement. In such cases, the existing management may have to be changed. Change of management will be essential in cases where restructuring of capital and liabilities is contemplated.

18.5 The measures enunciated in this policy would enable some of the units to come out of their present difficulty. However, where a unit has no expectation of becoming viable in a reasonable period of time, there may be no alternative but to allow the unit to close provided the interests of the workers are protected. Takeover by the Government or nationalisation of such sick units does not provide solution to the problems of sickness and the Government would not, as a rule, intervene in such cases.

18.6 In the process of revival of sick units and in the event of closure or liquidation, the interest of labour shall be fully protected. All possible avenues must be tried before retrenchment to minimise the social costs of transition implicit in the restructuring of the textile industry. Rationalisation of labour and revision of worknorms would need to be negotiated with labour to arrive at a satisfactory solution. The funds needed for payment of retrenchment benefit

to labour shall be part of **rehabilitation package** and loans needed for such compensation shall be provided on concessional terms. Displaced workers would be given priority in securing employment in other units under the same management or other industrial units in the same area. Concessional finance would be made available for providing opportunities of self-employment. Workers shall also be encouraged to form co-operatives to run part or whole of the units. Schemes shall be formulated for training and re-training of labour to facilitate redeployment.

18.7 It is of utmost importance that interest of the workers who might be displaced by permanent closure of units is safeguarded. For this purpose, schemes shall be formulated to provide relief for an interim period in addition to the statutory benefits. A Rehabilitation Fund for the workers of the textile industry would be created to provide relief to such workers for a limited period. Such a Fund shall, inter alia, be financed by a suitable cess on the textile industry.

18.8 It is necessary to monitor closely the performance of textile units to detect any sign of incipient sickness so that timely corrective measures can be taken. For this purpose, the monitoring mechanism at various levels shall be strengthened.

19.1 One of the main reasons for the present difficulties of the industry is inadequate modernisation and renovation of old and obsolete plant and machinery. Despite encouragement and incentives by the Government, the industry has only modernised to a limited extent. Government policies would aim to accelerate the pace of modernisation in the industry.

19.2 There has been very little modernisation in the ginning area, which has adversely affected the quality of cotton and hence the end-product of the industry. Expeditions replacement and modernisation of existing gins would receive priority. Concessional finance shall be made available for this purpose.

19.3 Modernisation in the spinning, weaving and processing sectors shall be undertaken on the basis of carefully identified needs of each unit as to installation of balancing equipment, renovation of existing machinery, replacement and technology upgradation.

19.4 For the purpose of modernisation, adequate funds would continue to be provided in adequate measure under the soft loan scheme of the IDBI. In order to enable the industry to generate internal resources for modernisation, a textile Modernisation Fund shall be created.

19.5 A national level Standing Advisory Committee on modernisation of the textile industry shall be set up, which would include representatives of management and labour as also suitable technical experts and representatives of financial institutions. This Committee shall identify on a continuous basis the needs of modernisation and the type of modernisation that the industry should adopt.

19.6 It will be ensured that in the process of implementation of modernisation programme, the interests of workers are adequately protected.

19.7 The indigenous textile machinery manufacturing industry shall be given encouragement to reduce costs, upgrade technology and improve the quality of machinery. However, liberal import of such textile machinery, which is not manufactured indigenously, shall be permitted at or near the international prices.

19.8 For expeditious modernisation of the handlooms, research for evolution of improved types of handlooms and adequate arrangements for ensuring swift and smooth transfer of technology from the research institutions to the handloom weavers will be given priority.

19.9 More powerloom service centres shall be established to enable the powerloom weavers to improve their skills in regard to maintenance of equipment, design development and quality of weaving.

19.10 The Textile Research Associations would be actively involved with the process of modernisation and its monitoring and their role expanded, so that they may also cater to the needs of the handlooms and powerlooms.

20. The National Textile Corporation contributes significantly to the total production of yarn and fabrics in the organised sector. A number of mills under the NTC have been able to eliminate cash losses through a programme of rehabilitation. Greater effort is needed to implement programmes of selective modernisation so that as many units as possible become profitable. The continued operation of units, which are incapable of becoming viable would mean a continued drain on scarce resources and such units or parts thereof may have to be closed down to prevent any further losses. In such cases, the interest of the workers would be adequately protected. With the implementation of a programme of modernisation of equipment, strengthening and improvement of management, raising productivity of labour and improvement of work-culture, it is expected that NTC would provide a stabilising influence and healthy competition in the textile industry.

21. Exports from the textile sector contribute a significant portion to the total foreign exchange earnings derived from exports. There are, however, certain constraints, both internal and external, which have meant that the full potential of textile exports has not yet been realised. In the international context, the Government shall strive to bring about a liberalisation of world trade in textiles which would alleviate the external constraints on our exports. In the domestic sphere, all necessary steps would be taken to exploit our comparative advantage in this sector and to make our exports of textiles more competitive in the world market in terms of both quality and prices. For this purpose, the framework

of policy would ensure that inputs for export production including capital goods, are made available at or near world prices. At the same time, it would be necessary to intensify efforts in the area of product and market development, reorient marketing strategy and create capabilities for fashion and design development. Exports of products from the handloom sector, including silk products, have considerable potential in the world market. All encouragement would be given to assist in the realisation of this potential. In so far as export product is an integral part of the total production base in the industry, the measures for restructuring and modernisation of the textile industry, outlined in this Statement, shall provide the necessary impetus to exports.

22. The Government would continue to lay emphasis on the development of sericulture on account of its employment potential in the rural areas, high income generating capacity and ability to earn valuable foreign exchange through exports. Encouragement and support will continue to be given to the Central Silk Board and the State Governments for rapid development of this industry in all parts of the country. Greater attention will be given to schemes relating to production of quality seeds, plantation of improved varieties and expansion of sericulture activities over larger areas and achieving a higher yield per hectare. The existing extension and training services for educating the farmers in the improved techniques of silkworm rearing and control of diseases would be strengthened. Efforts shall be made for the development of technology in reeling, weaving and processing for improving the quality of the silk fabrics.

23. Government would continue to promote the growth of the woollen sector in order to ensure adequate availability of woollens and blankets at reasonable prices to economically weaker sections, particularly those living in the hill regions of the country. Programmes would be undertaken to augment the indigenous raw wool production in terms of both quantity and quality. Since the indigenous raw wool production is not enough to meet the requirements of the industry, liberal policy regarding imports of quality wool as well as shoddy would be continued. Research and development programmes will be promoted so that cheaper and better quality woollen products are developed for the domestic as also export markets.

24. The knitting and apparel manufacturing sectors contribute significantly to employment generation and export earnings besides meeting the domestic demand for clothing. The Government shall pursue policies for strengthening, modernising and developing these sectors.

25. The existing marketing and distribution system of the industry would be reviewed to introduce changes, wherever necessary, in order to evolve a more efficient system which would reduce costs and margins and provide both consumer satisfaction and consumer protection. The institutional mechanism for market research would be strengthened.

26. The textile industry has been subjected to a number of controls and regulations, many of which have become irrelevant or unnecessary with the passage of time. Such controls would be reviewed for elimination, phasing out or modification, as the case may be.

outlined above would facilitate the necessary restructuring of the textile industry in India, would equip it to make an increasingly significant contribution to output, employment and exports in the country and would satisfy the clothing needs of all sections of the population.

27. Government hopes that the policy framework

J. K. BAGCHI, Jt. Secy.

